



संपादकीय

आप हमारे अपने

नक्सलियों से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आप हमारे अपने हैं। हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल हों। जब कोई नक्सली मारा जाता है, तो कोई भी खुश नहीं होता। दतेवाड़ा में बस्तर पंडुम महोत्सव में समापन समारोह में शाह ने कहा कि मार्च, 2026 तक नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नक्सलमुक्त घोषित गांवों को एक करोड़ रुपये की विकास निधि देने तथा नक्सलियों की सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित करने की बात भी उन्होंने की। शाह के बस्तर प्रवास के दरम्यान छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने हैदराबाद में सामूहिक समर्पण किया जिनमें बीस नक्सल माहिलाएं भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से 1967 में शुरू किसानों के विद्रोह को नक्सलवाद कहा गया। इसमें शामिल लोगों को नक्सलवादी या नक्सल कहा जाने लगा। इन्हें मुख्यतया वामपंथी आंदोलनों से जोड़ा जाता है जो माओवादी राजनीतिक विचारधारा का पालन करते हैं। सरकार के अनुसार देश में नक्सल प्रभावित जिले सत्रह से घट कर छह रह गए हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखण्ड और ओडिशा में इनकी जड़ें फैली हुई हैं। बिहार के विभिन्न जिलों को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बावजूद अभी भी दस जिलों में इनका प्रभाव है। सरकार के प्रति नाराजगी और बुनियादी जरूरियात की मांग को लेकर ये उग्र प्रदर्शन करते रहे हैं। पिछले दिनों नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने पर्चा जारी करके सरकार से युद्धविराम की मांग की। नक्सल प्रभावित इलाकों के नौजवान अब बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में अपना बक्त लगाना बेहतर मान रहे हैं। जान बचाने के लिए घने जंगलों में भटकने या सुरक्षा बलों का निशाना बनने को वे राजी नहीं हो रहे। गुरिला युद्ध की ट्रेनिंग लेकर हथियारबंद लड़ाकों को लगातार रिहाइशी इलाकों की तरफ जाने से रोका जा रहा है। दशकों से चले आ रहे इस सशस्त्र वामपंथी आंदोलन को नेस्तनाबूद करने को दृढ़संकल्पित केंद्र सरकार सफल होती दिख रही है। हालांकि ग्रामीण और बीहाड़ इलाकों तक विकास, सड़कें, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही रोजगार के साधनों की ठोस व्यवस्था ही नौजवानों को मतिभ्रम से दूर रख सकती है। मात्र ओजस्वी भाषणों के भरोसे उनके आवेग/गुरुसे को रोका जाना मुश्किल है।

આલર્ગો

कांग्रेस को 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं

अजोत द्विवे

अगर कांशिशां के लिए नंबर देना हा तो कांग्रेस को 10 मे से 10 नंबर दिए जा सकते हैं। कुछ समय पहले तक वह कोशिश भी नहीं कर रही थी। लेकिन अब पार्टी संगठन को बदलने और उसमें जोश भरने की गंभीर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व के बारे में धारणा बदलने की कोशिश हो रही है। पार्टी को नए समय की चुनौतियों और राजनीतिक मुद्दों के मुताबिक ढालने की कोशिश भी चल रही है। पुरानी विरासत को हासिल करने का प्रयास भी हो रहा है और सबसे ऊपर कांग्रेस का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कामयाबी की संभावना अभी नहीं दिख रही है लेकिन व्यक्ति के जीवन की तरह ही राजनीति में भी कई बार बहुत नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए कांग्रेस की कोशिशों का क्या हासिल होगा उसके बारे में समय बताएगा। यह कहना बहुत आसान है कि कांग्रेस लड़ना या जीतना भूल गई है या कांग्रेस की मारक क्षमता कम हो गई या नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए उसके पास कोई नेतृत्व नहीं है या कांग्रेस के अखिल भारतीय संगठन का ढाँचा चरमराया हुआ है। हकीकत यह है कि इसके बावजूद कांग्रेस लड़ रही है, लगातार पराजय और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व मैदान में टिका है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस व राहुल की असफलताओं पर विचार करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है और और और वह क्या क्या कर सकता है! सो, गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार, आठ अप्रैल से होने जा रहे दो दिन के कांग्रेस अधिवेशन से उत्तरे कांग्रेस नई तरीकाएँ पा उत्तर ताते नई तरात हैं। कांग्रेस

क बहान कांग्रेस का काशशा पर चोचा करने का जरूरत ह। कांग्रेस सभसे पहले तो अपनी विरासत को हासिल करने का प्रयास कर रही है। असल में 2014 में कांग्रेस जितनी बुरी तरह से हारी वह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। हारना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं थी लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पार्टी 44 सीट पर सिमट जाएगी। इतनी बुरी तरह से हारने की वजह से उसको संभलने में इतना समय लगा है। इस अवधि में वह पूरी तरह से सदमे में रही। कोई नया आइडिया तो पार्टी के पास नहीं ही था वह पुरानी विरासत भी भूल गई और भाजपा ने इसका फायदा उठाया। उसने कांग्रेस के महापुरुषों को अपना बना कर कांग्रेस की साख बिगाड़ी। प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी ने मदन मोहन मालवीय के परिजनों को अपना प्रस्तावक बनाया। उसने पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लालबहादुर शास्त्री और यहां तक कि महात्मा गांधी को भी अपना बताना और बनाना शुरू कर दिया। वास्तविकता यह है कि इनमें से लगभग सभी लोग भाजपा के पूर्ववर्ती संगठन और आरएसएस दोनों के विचारों के घनघोर विरोधी रहे हैं। अब जाकर कांग्रेस संभली है तो उसने अपनी विरासत हासिल करने का प्रयास शुरू किया है। कांग्रेस अपने दो दिन के अधिवेशन के पहले दिन आठ अप्रैल को अहमदाबाद के शाहीबाग में स्थित सरदार पटेल मेमोरियल में कार्य समिति की बैठक करेगी। दूसरे दिन नौ अप्रैल को साबरमती के किनारे कांग्रेस अधिवेशन का मुख्य कार्यक्रम होगा। कांग्रेस 61 साल के बाद गुजरात में अधिवेशन कर रही है और यह संयोग नहीं है कि इस साल सरदार पटेल की डेढ़ सौवीं जयंती मनाई जा रही है। सरदार की डेढ़ सौवीं जयंती पर कांग्रेस ने गुजरात में अधिवेशन का फैसला किया तो इसका कहीं न कहीं यह अर्थ है कि वह सरदार पटेल की विरासत को वापस हासिल करना चाहती है। कांग्रेस के बाद के नेताओं ने खास कर माधव सिंह सोलंकी ने कांग्रेस को खाम (केएचएम) यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम की राजनीति में समेटा था। इसका कुछ लाभ तो पार्टी को मिला लेकिन उसके बाद जब हार का सिलसिला शुरू हुआ तो यह समीकरण काम नहीं आया। अब कांग्रेस इस समीकरण से बाहर निकल कर आजादी के बाद के सबको साथ लेकर चलने के समीकरण पर काम कर रही है। विरासत वापस हासिल करने की कांशिश कांग्रेस ने पिछले साल दिसंबर के अंत में बेलगावी अधिवेशन से शुरू की।

કુલદીપ ચંદ અનિહોત્રી

नक्सलियों से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आप हमारे अपने हैं। हथियार डाल कर मुख्यधारा में सामिल हों। जब कोई नक्सली मारा जाता है, तो कोई भी खुश नहीं होता। दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम महोत्सव में समापन समारोह में शाह ने कहा कि मार्च, 2026 तक नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नक्सलमुक्त घोषित गांवों को एक करोड़ रुपये की विकास निधि देने तथा नक्सलियों की सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित करने की बात भी उन्होंने की। शाह के बस्तर प्रवास के दरम्यान छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने हैदराबाद में सामूहिक समर्पण किया जिनमें बीस नक्सल महिलाएं भी शामिल हैं। पश्चिम बंगल के नक्सलबाड़ी गांव से 1967 में शुरू किसानों के विद्रोह को नक्सलवाद कहा गया। इसमें शामिल लोगों को नक्सलवादी या नक्सल कहा जाने लगा। इन्हें मुख्यतया वामपंथी आंदोलनों से जोड़ा जाता है जो माओवादी राजनीतिक विचारधारा का पालन करते हैं। सरकार के अनुसार देश में नक्सल प्रभावित जिले सत्रह से घट कर छह रह गए हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखण्ड और ओडिशा में इनकी जड़ें फैली हुई हैं। बिहार के विभिन्न जिलों को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बावजूद अभी भी दस जिलों में इनका प्रभाव है। सरकार के प्रति नाराजगी और बुनियादी जरूरियात की मांग को लेकर ये उग्र प्रदर्शन करते रहे हैं। पिछले दिनों नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने पर्चा जारी करके सरकार से युद्धविराम की मांग की। नक्सल प्रभावित इलाकों के नौजवान अब बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में अपना वक्त लगाना बेहतर मान रहे हैं। जान बचाने के लिए घने जंगलों में भटकने या सुरक्षा बलों का निशाना बनने को वे राजी नहीं हो रहे। गुरुलिया युद्ध की ट्रेनिंग लेकर हथियारबंद लड़कों को लगातार रिहाइशी इलाकों की तरफ जाने से रोका जा रहा है। दशकों से चले आ रहे इस सशस्त्र वामपंथी आंदोलन को नेस्तनाबूद करने को दृढ़संकलित केंद्र सरकार सफल होती दिख रही है। हालांकि ग्रामीण और बीहड़ इलाकों तक विकास, सड़कें, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही रोजगार के साधनों की ठोस व्यवस्था ही नौजवानों को मतिध्रम से दूर रख सकती है। मात्र ओजस्वी भाषणों के भरोसे उनके आवेग/गुरुस्से को रोका जाना मुश्किल है।

A small yellow shrine or hut with red flags stands at the base of a large, light-colored rock face in a dry, rocky landscape.

का आयोजन किया था। उसमें उसने सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। महर्षि नारद घूमते हुए आए तो उन्होंने सती को बताया कि उसके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तब सती ने अपने पिता के इस यज्ञ में जाने का निर्णय कर लिया। शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण के कहीं जाना सम्मानजनक नहीं होता। लेकिन सती का तर्क था कि पिता के घर जाने के लिए भला पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता होती है? शिव के रोकने के बावजूद सती अपने पिता के इस यज्ञ समारोह में पहुंच गई। यज्ञ में सभी सगे संबंधी उपस्थित थे। सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा लिया कि आपने शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया। दक्ष ने सभी के सामने गुरुसे में आकर शंकर के लिए अपशब्द कहे। सती पिता के इस व्यवहार से अत्यंत आहत और अपमानित हुई और उसने वहीं यज्ञ अग्निकुंड में कूद कर अपने प्राण दे दिए। शंकर जी को इस दुर्घटना का पता चला। वे क्रोधोमर्त हो उठे। उनके गणों ने तांडव मचा दिया। सभी आमंत्रित अतिथि इधर-उधर भाग गए। यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव ने सती का शरीर अग्निकुंड से निकाला और उसे कंधे पर उठाकर चल पड़े। उनके दुःख का आवेग शांत नहीं हो रहा था। लगता था वे अपने क्रोध की अग्नि से सारे संसार को राख कर देंगे। जाहिर है इससे सभी को चिंता हुई। जब तक शंकर के कन्धे पर सती का शरीर रहेगा तब तक वे शांत नहीं होंगे। विष्णु ने इसका समाधान

फटकार खाकर भी नहीं सुधरी देश की पुलिस

यागद्र यागा

राजद्रोह कानून का मनमान प्रयाग तथा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की लक्षित गिरफ्तारियां इस बात को उजागर करती हैं कि पुलिसिंग प्रायः विधि के शासन के बजाय राजनीतिक हितों से प्रेरित होती है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2017 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत में पुलिस विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है नेताओं के हाथों की कठपुतली बनी पुलिस प्रणाली देश के आम लोगों का विश्वास जीतने में पूरी तरह नाकाम रही है। पुलिस का आचरण और व्यवहार आजादी के बाद भी सामंती बना हुआ है। अपराध रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस के अपराधियों की तरह आचरण करने से वर्दी दागदार हो रही है। पुलिस राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में होने के कारण सत्तारूढ़ दलों के इशारों के बागेर काम नहीं करती है। ऐसे ही हालात पुलिस पर पक्षपात करने के जिम्मेदार हैं। अधीनस्थ से लेकर देश की शीर्ष अदालत ने कई बार पुलिस की कारगुजारियों को उजागर किया है। इसके बावजूद पुलिस के रवैये में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मामले में आपराधिक कानून लगाने पर उत्तरप्रदेश (यूपी) पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यूपी पुलिस की ओर से दीवानी मामलों में दर्ज की गई प्राथमिकियों पर गौर करने से पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। पुलिस में खुद अपराध बन बठा ह। पजाब के चाचत मांगा सेक्स स्कैंडल में मोहाली स्थित कोर्ट ने 4 पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई है। मोगा सेक्स स्कैंडल साल 2007 में सुर्खियों में आया। उस समय पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन की सरकार थी। इस स्कैंडल में कई हाई प्रोफेशल राजनेता और सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल थे। ये सब मिलकर अमीर लोगों को देह व्यापार में फँसाते थे। पुलिस की कारगुजारियों का पर्दाफश सुप्रीम कोर्ट ने एक मृत्युंदंड के मामले में भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप में निचली अदालत से मौत की सजा प्राप्त एक युवक को बरी करते हुए पुलिस प्रक्रिया पर तीखी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सभी फेरेंसिक और गवाहों की रिपोर्टों की बारीकी से समीक्षा की और पाया कि आरोपी के खिलाफोंई विश्वसनीय सबूत नहीं था। इस तरह एक निरोध व्यक्ति ने 10 साल फँसी की सजा के साए में जेल में बिताए, जबकि पुलिस और न्यायिक व्यवस्था की नाकामी साफ नजर आई। सुप्रीम कोर्ट पुलिस और सत्तारूढ़ दलों के नापाक गठजोड़ को कई बार उजागर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहे एनवी रमना ने एक मामले में कहा था कि देखा जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर करते हैं और सत्ता पक्ष के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बात ह। दश में इस तरह का जा ट्रॉड दख रहा है वह काफ परेशान करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा था कि इसके लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह कानून के शासन पर टिकी रहे। वह सत्ता और विपक्ष किसी के साथ न होकर स्वतंत्र रूप से काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी। पाल के खिलाफ पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के इशारे पर आय से अधिक सम्पत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कोलकाता चिकित्सक के बलात्कार-हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोलकाता पुलिस ने इस मामले को जिस तरह से संभाला, वह कुछ ऐसा है जो उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्षों में नहीं देखा। शीर्ष अदालत ने अप्राकृतिक मौत के मामले के पंजीकरण में देरी की आलोचना की। पुलिस की मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर देश में कई सुधार करने के प्रयास हुए हैं, किन्तु सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने ऐसे प्रयासों को नाकाम करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। स्वतंत्रता के बाद से ही, इस व्यवस्था में सुधार की मांग उठती रही है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार, कोर्ट ने गठन किया गया। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और वर्ष 1971 में बनी गोर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें धूल खा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधारों पर कई निर्देश दिए, जिनमें यह भी शामिल था कि राज्य पुलिस प्रमुखों का दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। निर्देशों में राज्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल और कानून एवं व्यवस्था से जंच को अलग करना शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी राज्यों ने पालना नहीं की। इसे देश के सभी राज्यों ने या तो लागू नहीं किया या फिर निर्देशों को अधे-अधेरे तरीके से लागू किया गया। ताकि पुलिस में सत्तारूढ़ दलों का हस्तक्षेप पूरी तरह से बना रह सके। इन सिफारिशों को लागू नहीं करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 72 प्रतिशत पुलिस अधिकारियों ने मामलों की जंच करते समय राजनीतिक दबाव का अनुभव किया है। पुलिस ग्रायः अत्यधिक बल का प्रयोग करती है, विशेषक विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अर्शांति से निपटने में। अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक पिछले पांच वर्षों में देश भर में पुलिस हिरासत में मौत के कुल 669 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा भारत में अपराध विज्ञान के क्षेत्र में इतने सारे अवसर होने के बावजूद प्रति 0.1 मिलियन जनसंख्या पर केवल 0.33 फेरेंसिक वैज्ञानिक हैं।

भारतीय राष्ट्र के सामने चुनौतियां...

कुलभूषण उपमन्यु

A wide-angle photograph capturing a massive crowd of people from behind, silhouetted against a vibrant sunset. The sky is filled with warm orange and yellow hues. Numerous Indian flags are held aloft, their tricolors catching some light. Many individuals in the crowd have their right hands raised, palm facing forward, in a common gesture of protest or a call to action. The scene conveys a sense of collective energy and national identity.



वहां भी गलती का शिकार हो गए। जब दो धर्मों के आधार पर देश बांट दिए गए तो बेहतर यही होता कि शान्तिपूर्ण तरीके से गैर मुस्लिम भारत में आ जाते और मुसलमान पक्षिस्तान चले जाते। किन्तु हिंदू-मुस्लिम आबादियों का आदान-प्रदान भयंकर मारकाट में बदल गया। अंग्रेज सेना जानबूझ कर मूकदर्शक बनी रही। आबादियों का पूर्ण प्रत्यर्पण भी न हो सका और आज दिन तक आपसी टकरावों की समस्या से देश को जूझना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय नेतृत्व का उस समय का फैसला मानवतावादी था किन्तु सांप्रदायिक अहंकार में उसके महत्व को समझने में भारतीय राष्ट्र असफल सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में इस समस्या को ऐतिहासिक बोझ से बाहर निकल कर मानवतावाद से ही हल किया जा सकता है, जो दोतरफ़ ही होना चाहिए। मुसलमानों को भी यह समझना होगा कि हिंदू बहुल देश में आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, किन्तु आप भी हिंदू मान्यताओं के पालन में बाधक न बनें। यदि आप मूर्ति पूजा, भजन गाने, शंख, घटे की आवाज और नाचने-गाने का बुरा मानने लगेंगे तो झगड़े कैसे रुकेंगे। हमें एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने, मुबारक देने की संस्कृति विकसित करनी होगी। रहीम, रसखान, खुसरो सरीखे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनसे मिलजल कर रहना और संवेदनिक दर्जा दिया गया किन्तु अभी तक भी वे शासकीय दिशा निर्देशों की गुलाम ही हैं। क्योंकि वे जमीन से नहीं उआई गई, आरोपित की गई हैं। उन्हें अपने आत्मविश्वास को आधार बनाने में न जाने अभी कितना समय लगेगा। पाश्चात्य सोच में प्रशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन यह होने भी देगा या नहीं। धर्मनिरपेक्षता दूसरी बड़ी चुनौती है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म सम्भाव ही हो सकता है। यहां धर्म मुक्त शासन संभव नहीं है। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष शब्द सर्विधान में नहीं रखा था जो बाद में इमरजेंसी में इंदिरा जी के समय में डाला गया।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त

रायपुर (विश्व परिवार)। राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रमेन डेका द्वारा प्रोफेसर विजय कुमार गोयल, रिटायर्ड प्रिंसिपल संत गोविंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष एवं डॉ. व्यास दुबे, सेवानिवृत्त प्राचीनाक एवं विभागाधारी (सांखिकी अध्ययन शाला) को पूर्णकालिक सदस्य (अकादमिक) नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अधिनियम 2005 की धारा 36 की उपधारा (4) एवं (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। इस आशय का आदेश 15 अप्रैल को गजबन्वन सचिवालय से जारी किया गया।

फ्लैट्स आवंटन के बाद एक भी किस्त जमा नहीं की, कौशल्या माता विहार के फ्लैट्स 7 दिन बाद होंगे निरस्त

रायपुर (विश्व परिवार)। कौशल्या माता विहार योजना (कमल विहार) में लगावा एक साल पहले से आवंटित फ्लैट्स के एक भी किस्त जमा नहीं करने वाले आवंटितियों के फ्लैट्स आगामी 7 दिनों के बाद निरस्त कर दिए जाएंगे। रायपुर विकास प्रशासन द्वारा फोन, एसएमएस तथा डाक से सूचना देने के बाद भी आवंटितियों द्वारा पहली किस्त की राशि जमा नहीं की है। प्राधिकरण ने आवंटितियों को 7 कार्य दिवस अर्थात् 28 अप्रैल 2025 तक संपूर्ण बकाया राशि जमा करने के लिए अंतिम सूचना जारी कर दी है। इसके बाद जिनकी राशि जमा नहीं होगी उन सभी फ्लैट्स का आवंटन रद्द कर उसे पुनः विकासन के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। प्राधिकरण प्रशासन का यह भी माना है कि ऐसे कई आवंटितियों ने एजेंटों के माध्यम से पुनः निवेश हेतु आवंटन कराया है। फ्लैट्स नहीं मिल पा रहा है।

कुगदा गेट रेलवे सम्पार फाटक पर मरम्मत के लिये सड़क यातायात बंद रहेगा

रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर रेल मंडल कुम्हारी-सीकेबन के मध्य सम्पार फाटक क्रमांक 430(कि.मी.842/7-9) रेल पथ में अपलाइन में दिनांक 17.04.2025 को सुबह 08:00 बजे से दिनांक 22.04.2025 सुबह 08:00 बजे तक सड़क यातायात का आवागमन बंद रहेगा। आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण सम्पार फाटक से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। सम्पार फाटक की मरम्मत करना रेल यातायात व यात्रियों की संरक्षा की दृष्टि से अंत आवश्यक है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे ग्राम पंचायत हल्ला कचोरा के आश्रित ग्राम शासन कचोरा

रायपुर (विश्व परिवार)। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्राम पंचायत हल्ला कचोरा के आश्रित ग्राम शासन कचोरा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण विशेष परवाइड के अंतर्गत सर्वे किया, जिसके तहत पात्र हिंगारियों के घरों का सर्वेक्षण कर उन्हें आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कई घरों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उहाँने भरोसा दिलाया कि पात्र सभी व्यक्तियों को जल्द ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उहाँने कहा, अब सरकार ने आवास योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया है। जो भी पात्र हैं, उहाँ फ्लैट्स नहीं मिल पा रहा है।

रायपुर (विश्व परिवार)। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्राम पंचायत हल्ला कचोरा के आश्रित ग्राम शासन कचोरा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण विशेष परवाइड के अंतर्गत सर्वे किया, जिसके तहत पात्र हिंगारियों के घरों का सर्वेक्षण कर उन्हें आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कई घरों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उहाँने भरोसा दिलाया कि पात्र सभी व्यक्तियों को जल्द ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उहाँने कहा, अब सरकार ने आवास योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया है। जो भी पात्र हैं, उहाँ फ्लैट्स नहीं मिल पा रहा है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने मण्डल की आवासीय गतिविधियों एवं योजनाओं की समीक्षा की।

रायपुर (विश्व परिवार)। अनुराग सिंह देव, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के दिनांक 15 अप्रैल 2025 को आयुक्त एवं मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मण्डल की आवासीय गतिविधियों, योजनाओं एवं नियोग कार्यों की समीक्षा की।

आयुक्त कुमार कुमार ने हाऊसिंग बोर्ड के गठन, सेंट-आप, मण्डल कुम्हारी गृह निर्माण मण्डल के दिनांक 15 अप्रैल 2025 को आयुक्त एवं मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मण्डल की आवासीय गतिविधियों, योजनाओं एवं नियोग कार्यों की समीक्षा की।

आयुक्त कुमार कुमार ने हाऊसिंग बोर्ड के गठन, सेंट-आप, मण्डल कुम्हारी गृह निर्माण मण्डल के दिनांक 15 अप्रैल 2025 को आयुक्त एवं मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मण्डल की आवासीय गतिविधियों, योजनाओं एवं नियोग कार्यों की समीक्षा की।

उहाँने मण्डल के नियोग कार्यों की समी